श्री युवराज (कटिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

1. भारत सरकार के भवनों में भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चल रहे कैन्टीन विभागीय हों अथवा सहकारी— इनमें कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन, सुविधायें आदि का अभाव, इनकी स्थिति दयनीय है ।

2. आजादी के 32 वर्षों बाद भी कैन्टीन मजदूर ही एक ऐसा वर्ग रहा है जिसके लिए सरकार ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया । गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं भारत सरकार के अनेकों विभागों के रहते हुए भी कैन्टीन श्रमिकों का शोषण होता रहा है । सरकार ने खेतिहर मजदूर, ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले मजदूर, दूकान एवं होटलों में कार्यरत श्रमिकों एवं गृह कार्य कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून बनाया, उनकी सुविधाओं के प्रति सरकार ने ध्यान दिया, उनका शोषण रोका लेकिन कैन्टीन मजदूरों को इन सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया जबकि इनका रोज का काम सरकारी अधिकारियों की सेवा करना ही है ।

अपनी बातों को रखने के लिए यह अधिकारी वर्ग कैन्टीन की व्यवस्था की अवसर बदली करते हैं, कभी सहकारी ढंग से चलाने की नीति तो कभी विभागीय चलाने की नीति अपनाते रहते हैं । परिणामस्वरूप इसके कार्यरत कर्मचारी रातों रात निकाल दिए जाते हैं । और नयी भर्ती शुरू हो जाती है । मालूम पड़ता है कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं ।

दूसरी ओर ये सरकारी अधिकारी अपने हकों के लिए सरकार से लड़ते हैं कमीशन का निर्माण करते हैं और अन्य अनेकों पद्धतियों से सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं । सरकार भी इनकी मांगें मान लेती है, लेकिन इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत कैन्टीन कर्मचारी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । देश में महंगाई बढ़े तो महंगाई भत्ता इन्हें मिले, तनख्वाह बढ़े तो इन्हें मिले, शहरी भत्ता मकान भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और अन्य अनेकों भत्ते तो इन्हें ही मिलें लेकिन कैन्टीन कर्मचारी अपने परिवार के साथ भूखा रहे । इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है ।

इसी प्रसंग में कुछ विभागों की दोरंगी नीति की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इण्डियन पेट्रो कैमीकल्स इण्डियन आयल, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स, रेलवे आदि ने तो अपने विभाग में कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी विभागीय कर्मचारी बना दिया है । इनके जैसे कार्य करने वाली संस्था टी बोर्ड एवं काफी बोर्ड का भी उदाहरण सामने है । सरकार ने उन्हें अपने कर्मचारी माना है और वे सारी सहूलियतें दी हैं जो सरकारी अधिकारियों को मिलती हैं, लेकिन जब कभी कैन्टीन मजदूरों का सवाल उठाया गया है, तो इन का मजाक ही उड़ाया गया ।

जनता सरकार ने अपने दो वर्ष के शासन में ही ऐसे अनेकों तरह के कर्मचारियों को अनेक सुविधायें दी हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया है और जो बचे हैं उनके लिये भी एक ठोस कदम उठाने का निश्चय किया हुआ है । फिर भी ये कैन्टीन मजदूर उपेक्षित ही हैं ।

कैन्टीन मजदूर सभा ने दिनांक 9-3-79 को माननीय गृह मंत्री श्री एच0 एम0 पटेल जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिस में मांग की थी कि इन कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी बनाया जाये और इन्हें वे सारी सुविधायें दी जावें जो सरकारी कर्मचारी को भारत सरकार देती है । लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से कोई भी ठोस कदम उपरोक्त मांगों की पूर्ति के लिये अभी तक नहीं उठाया गया है । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे तथा उनकी मांगों को मंजूर करा कर उन्हें सरकारी कर्मचारी बनायेंगे ।

(ii) REPORTED RACKET IN COMMERCIAL AND RESIDENTIAL REAL ESTATE BUSINESS IN THE CAPITAL.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: (*Azamgarh*): *Mr. Chairman, Sir*, there is a racket in operation for a number of years which is being run by some promoters and brokers in commercial and residential real estate business in the Capital. A very large number of officials in the works and Housing Ministry, D.D.A. and local bodies are suspected to be involved in the racket. All these people, combined together, have defrauded the exchequer of crores of rupees. It came to light only when the Income-tax Intelligence authorities came to know of some suspicious entries in the accounts submit-

(Shrimati Mohsina Kidwai)

ted by these promoters and builders of multi-storeyed palatial buildings. Huge amounts have been shown as 'conversion charges' paid to an office under works, and Housing Ministry, whereas many plans for conversion were got cleared without paying a single paisa as required by law, but the underhand deals and connivance between the corrupt officials and the concerned people made the exchequer poorer by crores of rupees. I would like the Minister to take the House into confidence and tell us as to the number and names of the suspects and also the amount of money they have not paid to the Government, and the name and number of firms whose cases have been asked to be reopened by the Finance Ministry. I would like to know from the Minister as to what action has been taken against the guilty whether during investigation many a 'benami' sales have come to light and it has also been revealed that a coterie of financiers, promoters and brokers have corrupted the officials and have an iron-handed control over them. I would urge upon the Government to suspend those officials in Works and Housing Ministry, D.D.A. and New Delhi Municipal Committee, along with some bank managers against whom *prima facie* cases have been established. It is a very serious matter involving crores of rupees and a large number of Government officials. So, the Minister should make a statement in the House.

(iii) KUDREMUKH IRON ORE PROJECT IN KARNATAKA.

SHRI B. RACHAIAH (Chamarajanagar): Under Rule 377, I wish to raise the following matter of urgent public importance.

With the revolutionary upheaval in Iran, the Indo-Iran joint ventures have almost come to stand still. In particular, I would refer to the stoppage of oil from Iran, which has led to unprecedented problems in our country. We are in the process of introducing rationing of petroleum products for personal consumption in the interest of nation's industrial development. Some of the States have already introduced rationing of petroleum products.

In view of massive increase in the cost of imports of crude oil from other Arab nations to the tune of Rs. 500/- crores annually, there is also a proposal to increase the price of petrol.

In this background, Sir, I would refer to the Kudremukh Iron Ore project, which is entirely dependent on financial commitment of Iran. This is a prestigious project of not only Karnataka but of the whole country. We are on the horns of dilemma. We have to supply iron ore only to Iran, as per the terms of the bilateral agreement. For the completion of the project, we have to depend on Iran. Now, besides the unsettled conditions in Iran, there is a slump in the international iron ore market, which is bound to have serious repercussion on Indo-Iran deal. Secondly, it is apprehended that, on account of non-availability of shipping, the only mode of transporting iron ore, we may default in our supplies. Thirdly, in view of the reported monetary bankruptcy of Iran, Iran may not be able to fulfil its commitment of aid to Kudremukh project, in which case, the fate of the project would hang in suspended animation. There is an air of uncertainty enveloping the entire project.

The Janata Government's handling of Indo-Iran relationship does not redound to its credit. It is also inexplicable as to what is Government of India's approach to bilateral trade agreement with the former Government of Iran.

(iv) SUPPLY OF FOODGRAINS TO 'FOOD FOR WORK SCHEMES'.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): The F.C.I. is supplying foodgrains to food for work schemes in the various States of the country. *But it is not supplying them in time